एक हफ्ते में डीसी यशपाल के काम का कैसे आकलन कर लिया चीफ सेक्रेटरी ने !

विजय वर्धन ने तारीफों के पुल बांधे, बाकी आईएएस अफसर हुए हैरान

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: एक आईएएस अफसर 29 अप्रैल की आधीरात को वापस लौटकर फिर से पदभार ग्रहण करता है और 3 मई को हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन उस आईएएस अफसर की शान में कसीदे पढ़ने वाला पत्र जारी कर देते हैं कि उन्होंने कोरोना में बहुत शानदार काम किया है। 3 मई को जारी हुआ यह पत्र 9 मई को फरीदाबाद में मीडिया को भी मिलता है और उसके बाद जाहिर है कि मीडिया भी उस आईएएस की तारीफ में जुट जाता है। जानना चाहेंगे उस अफसर का नाम,...उनका नाम है यशपाल यादव जो फरीदाबाद के डीसी हैं। लेकिन हरियाणा के आईएएस अफसरों में इस पत्र को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई है, वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग से लौटे किसी अफसर के काम को एक हफ्ते में देखकर तय हो सकता है कि उस अफसर ने बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी अफसर के काम का आकलन एक हफ्ते में नहीं हो सकता।

यशपाल को वापस बुलाया

यशपाल यादव की ट्रेनिंग मार्च 2021 में तय थी लेकिन कोरोना की वजह से हरियाणा सरकार ने उन्हें ट्रेनिंग पर नहीं भेजने का फैसला किया। पाठकों को याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर ने मार्च में जोर नहीं पकड़ा था। यानी डीसी यशपाल यादव को आराम से ट्रेनिंग पर सरकार भेज

यशपाल यादव

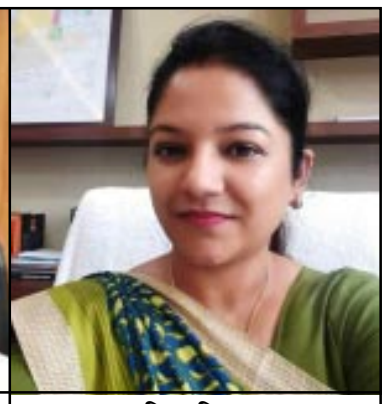

गरिमा मित्तल

सकती थी। लेकिन 3 अप्रैल से जब दूसरी लहर ने फरीदाबाद समेत देशभर को दहलाना शुरू किया तो हरियाणा सरकार ने 8 अप्रैल को आदेश जारी कर यशपाल यादव को ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहा। उनकी जगह हूडा फरीदाबाद के प्रशासक कृष्ण कुमार को डीसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया गया। यशपाल यादव इंतजार करते रहे कि कृष्ण कुमार आकर पदभार संभालें तो वो ट्रेनिंग पर रवाना हों। और सरकार की अक्लमंदी देखिए कि नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) कमिश्नर पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई, जबकि वहां का अतिरिक्त कार्यभार भी यशपाल यादव के पास था।

शहर में कोरोना बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ अफरातफरी फैलती जा रही थी। प्रशासन कहीं नजर नहीं आता था।

कोई आईएएस जब डीसी का पदभार संभालने को राजी नहीं हुआ तो सरकार ने 19 अप्रैल को नया आदेश जारी किया। इस आदेश में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी एफएमडीए की सीईओ गरिमा मित्तल को डीसी फरीदाबाद का चार्ज भी दे दिया गया। लेकिन इस बार सरकार ने यह अक्लमंदी दिखाई कि एमसीएफ के कमिश्नर पद पर जितेन्द्र यादव की नियुक्ति कर दी। यह नियुक्ति यशपाल यादव के ट्रेनिंग पर जाने की वजह से की गई, इसे आदेश में बाकायदा दर्ज किया गया। शहर में कोरोना चरम पर पहुंच जाता है।

गरिमा मित्तल डीसी का पदभार संभालने के बाद एक्शन में आ जाती हैं और तेजी से हालात को काबू करने के लिए अफसरों की टीम बनाती हैं, दौरे शुरू कर देती हैं। इसी दौरान मजदूर मोर्चा में छायंसा स्थित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के बंद होने और कोरोना काल में उसे इस्तेमाल न किए जाने की खबर छपती है तो मुख्यमंत्री फौरन 26 अप्रैल को छायंसा आने का प्रोग्राम बनाते हैं। यहां पर उन्हें कुछ लोग डीसी इंचार्ज गरिमा मित्तल के बारे में न जाने क्या फीडबैक देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फौरन चीफ सेक्रेटरी से यशपाल यादव को ट्रेनिंग से वापस बुलाने का निर्देश देते हैं। यशपाल यादव से कहा जाता है कि वह फरीदाबाद जब भी पहुंचे, सबसे पहले सीधे जाकर डीसी का कार्यभार ग्रहण करें। यशपाल यादव 29 अप्रैल को फरीदाबाद देर रात पहुंचते हैं और उसी समय डीसी का कार्यभार गरिमा मित्तल से वापस ले लेते हैं।

विजय वर्धन के पत्र के मायने

मुख्य सचिव विजय वर्धन का 3 मई को यशपाल यादव के लिए लिखा गया तारीफ का पत्र दरअसल यशपाल के ही रसूख को बताता है। यशपाल मुख्यमंत्री के बहुत प्रिय अफसरों में हैं। उनके चाचा भाजपा विधायक हैं और परिवार में कई आईएएस हैं। एक तरह से हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में यशपाल यादव काफी वजनदार हैं। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी क्यों न यशपाल यादव की तारीफ करेंगे। लेकिन बहुत सारे आईएएस अफसरों का कहना है कि मुख्य सचिव ने ऐसे प्रशंसा पत्र कितने अफसरों को जारी किए हैं। अगर जारी किए गए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया। इन अफसरों का यह भी कहना है कि मान लिया कि डीसी फरीदाबाद यशपाल यादव बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर उनके काम करने का इम्पैक्ट (असर) क्यों नहीं दिख रहा है। वह सारा दिन भागदौड़ करते हैं। लोकसंपर्क विभाग उनकी हर गतिविधि का प्रेसनोट जारी कर देता है। इन प्रेसनोटों और मीडिया में छप रही खबरों के हिसाब से तो लगता है कि डीसी फरीदाबाद वाकई तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं। नामी प्राइवेट अस्पतालों की बदमाशी पर अंकुश न लगा पाना फरीदाबाद के डीसी की सबसे बड़ी विफलता है। फरीदाबाद के मध्यम वर्ग ने इन नामी प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना काल में लूट की दुकान पाया।

गरिमा मित्तल रहीं फायदे में

एमसीएफ में कुछ कर दिखाने और तमाम तरह की संभावनाओं के मद्देनजर आमतौर पर आईएएस अफसर यहां आना चाहते हैं। डीसी रहते हुए जब यशपाल यादव के पास यहां का चार्ज था तो उनका मन यहां काफी लगता था। उन्होंने टैक्स रिकवरी में दिलचस्पी ली, इससे एमसीएफ के पास काफी टैक्स आया। लेकिन इधर जब अफसरों को इधर से उधर करने का सिलसिला चला तो गरिमा मित्तल ने 30 अप्रैल को एमसीएफ के कमिश्नर पद को हासिल कर लिया।

उन्होंने यशपाल यादव से चार्ज लिया था। हालांकि इस दौरान एमसीएफ में एक-दो और आईएएस की नियुक्ति की गई लेकिन उन्होंने यहां आने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस तरह फरीदाबाद में गरिमा मित्तल एकमात्र आईएएस हैं, जिनके पास तीन एजेंसियों का कार्यभार है। स्मार्ट फरीदाबाद प्रोजेक्ट और फरीदाबाद म्युनिस्पल डेलललमेंट अथॉरिटी के बाद एमसीएफ भी आ गया है। तीनों ही एजेंसियों के पास शहर को चमकाने का काम है। अब देखना है कि एक ही अफसर का तीनों का इंचार्ज बनने पर कितना सुधार हो पाता है।

1300 बच्चों का मिड डे मिल कहां गया डीपीसी मुनेश चौधरी साहिबा

फरीदाबाद के 46 सेंटरों पर प्रवासी मजदूरों के गरीब बच्चे भूखे रहे

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: कोई अधिकारी स्कूल के बच्चों को, प्रवासी मजदूरों के या आउट स्टेशन सेंटरों (ओएससी) में बच्चों को मिड डे मील न बांटे तो सुप्रीम कोर्ट की नजर में बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन फरीदाबाद में तैनात जिला परियोजना अधिकारी (डीपीसी) में कार्यरत अधिकारी मुनेश चौधरी को न तो सुप्रीम कोर्ट का और न ही हरियाणा सरकार का कोई खौफ है। डीपीसी मुनेश चौधरी ने पिछले साल यानी 2020 में सरकार की तरफ से भेजा गया मिड डे मील का कोटा न तो उठाया और न ही फरीदाबाद में जिले में बांटा। मुनेश चौधरी के खिलाफ पहले ही शिकायतें आती रही हैं लेकिन शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक के अधिकारी किसी भी कार्रवाई में रोड़े अटका देते हैं।

मुनेश चौधरी को गरीब बच्चों की फिक्र नहीं

हर जिले में डीपीसी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत काम करते हैं। इनका काम है गरीब बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाना। इसके लिए हरियाणा सरकार इन्हें अच्छा खासा बजट देती है और संसाधन मुहैया कराती है। लेकिन फरीदाबाद में डीपीसी मुनेश चौधरी ने इसे लालफीताशाही में तब्दील कर दिया है।

फरीदाबाद में प्रवासी मजदूरों के बच्चों, भट्ठा मजदूरों के बच्चों, झुग्गी-झोंपडियों में रहने वाले 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए 46 सेंटर खोले गए हैं। ऐसे वर्ग के बच्चों को यहां छह महीने तक सिखा-पढ़ाकर सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है। फरीदाबाद जिले में ऐसे सेंटरों में करीब 1300 बच्चे पढ़ रहे हैं। डीपीसी का काम है इन सेंटरों पर तैनात एजुकेशन वालंटियर (शिक्षा कार्यकर्ता) को सैलरी देना, बजट प्रावधान का सामान देना और सबसे आवश्यक है मिड डे मील देना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मिड डे मील सबसे ज्यादा आवश्यक है और यह बच्चों का हक है। एक भी बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए। लेकिन फरीदाबाद की

डीपीसी मुनेश चौधरी ने 2020 में 1300 बच्चों का मिड डे मील सरकार से उठाया ही नहीं और ही शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी। इस तरह कोरोना काल में फरीदाबाद के 46 सेंटरों के 1300 बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला और वे भूखे रहे।

एजुकेशन वालंटियर्स की आड़ में घोटाला

डीपीसी मुनेश चौधरी ने पिछले साल का मिड डे मील तो 1300 बच्चों को बांटा ही नहीं लेकिन दूसरी तरफ उसने इसी दौरान यानी 2020 में 46 एजुकेशन वालंटियर्स (ईवी) को 4 लाख 14 हजार वेतन बांट दिया। एक वालंटियर्स की सैलरी 9000 हजार रुपये हैं। हरियाणा सरकार एक सेंटर पर 70 हजार 500 रुपये खर्च करती है, जिसमें इनके वेतन का नौ हजार भी शामिल है। इस तरह फरीदाबाद में अकेले एक डीपीसी को 46 सेंटरों के लिए 32 लाख 43 हजार रुपये का फंड मिला। इसमें 500 रुपये की स्टेशनरी हर बच्चे को देने का भी निर्देश है। 46 सेंटर और 1300 बच्चों का आंकड़ा सरकारी कागजों में दर्ज है। लेकिन छानबीन बताती है कि अधिकांश सेंटरों को एजुकेशन वालंटियर्स डीपीसी के चहेते शिक्षकों के रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया है। स्पष्ट है कि ये नौ हजार रुपये उस शिक्षक की जेब में जा रहे होंगे, जिसने डीपीसी मुनेश चौधरी को उनके नाम दिए होंगे। तमाम सेंटरों पर पर्याप्त बच्चों के न होने की भी शिकायतें मिली हैं। लेकिन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डीपीसी मुनेश चौधरी की है जो वो करती ही नहीं हैं। नियम ये है कि एक ईवी सिर्फ 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन कई सारे ईवी लंबे समय से चल रहे हैं। इस तरह फरीदाबाद में डीपीसी दफ्तर शिक्षा घोटाले का सबसे बड़ा सेंटर बनकर रह गया है। इसी तरह 'हुमाना' नाम की एक एनजीओ को ऐसे बच्चों को सेंटर तक लाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। यह एनजीओ बच्चों का सर्वे कर डीपीसी को आंकड़ा देती है। 'हुमाना' ही ऐसे बच्चों को सेंटर तक लाती है। लेकिन यह सब एक गड़बड़झाला बनकर रह गया है। हुमाना एनजीओ के काम की मॉनिटरिंग भी डीपीसी नहीं कर पातीं।

हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने 15 अप्रैल को चंडीगढ़ में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर मिड डे मील बांटे जाने की योजना की समीक्षा की थी। इस बैठक के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गये थे कि सभी डीपीसी में मिड डे मील का बांटा जाना अनिवार्य है और इस संबंध में 2020 से अब तक कहां-कहां बांटा गया है, उसकी पूरी सूचना चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी जाए। ताकि हरियाणा सरकार उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दे सके। द चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मिड डे मील को लेकर एक याचिका दायर कर रखी है, जिसके जवाब में हरियाणा को सारी जानकारी अदालत को देनी है। हरियाणा सरकार ने डीसी फरीदाबाद से भी मिड डे मील के संबंध में डीपीसी के क्रियाकलाप की जानकारी मांगी थी।

बड़े अफसर मुनीश का करते हैं बचाव

डीपीसी मुनेश चौधरी मिड डे मील बांटे या न बांटे, बड़े अधिकारियों का निर्देश रहता है कि मुनेश चौधरी को कोई कुछ भी न कहे। जिला प्रशासन का एक उच्चाधिकारी तो स्पष्ट रूप से मुनेश चौधरी के पक्ष में खड़ा हो जाता है और उसके खिलाफ किसी भी शिकायत को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसी तरह शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मुनेश चौधरी की पैरवी में जुटे रहते हैं। फरीदाबाद में डीपीसी के मिड डे मील न बांटने का मामला अगर कोई एनजीओ अदालत में ले गया तो न सिर्फ मुनीश चौधरी बल्कि और भी कई बड़े अधिकारी घोर लापरवाही के इस मामले में लपेट लिए जाएंगे। अभी तक यह साफ नहीं है कि मुनेश चौधरी ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में क्या जवाब दिया है। इस संबंध में कोरोना का अगर बहाना बनाया गया तो अदालत ने पहले ही साफ कर दिया है कि मिड डे मील बांटने की आड़ में कोरोना फैलने का बहाना नहीं चलने वाला है।

शोक संदेश

अत्यंत दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा हैं कि मेरे घर के चिराग़ बड़े पुत्र दीपक शर्मा का कोरोना महामारी से देव लोक गमन 8/5/2021 को हो गया है जिनका दशगात्र 17/5/2021 को एंव त्रयोदशी संस्कार व गंगाजली पूजन 19/5/2021 को है ।

शोकाकुल परिवार

गिरीश चंद्र शर्मा (पिता) उमा शर्मा (माँ)
सुनील शर्मा (छोटा भाई) दीक्षा शर्मा (पत्नी)
आदित्रि शर्मा (पुत्री) अचिंत्य शर्मा (भतीजा)
पल्लवी शर्मा (छोटे भाई की पत्नी) एवं समस्त शर्मा परिवार

पता- 1210 सेक्टर 7-डी फ़रीदाबाद -121006

मोबाइल नम्बर : 9811157562,9999446252,8790813311

SOS

आज मजदूर मोर्चा अपने कठिनतम दौर से गुजर रहा है। यदि समय रहते सुधी पाठकों का सहयोग न मिल पाया तो इस निर्भीक एवं जुझारू आवाज का जीवित रहना दूभर हो जायेगा। इसलिये पाठकों से विनम्र निवेदन है कि यथाशक्ति आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad